भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2692

मंगलवार, दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

ओडिशा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना

2692 श्री दिलीप राय:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ओडिशा में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर प्रणाली को बढ़ावा दे रही है;

(ख) अब तक कितने सरकारी भवनों को इसमें शामिल किया गया है;

(ग) ओडिशा राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य और रूपरेखा क्या-क्या हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ओडिशा राज्य सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे अपने विभागों और संस्थानों को ज़रूरी निर्देश जारी करें, ताकि उनके भवनों की खाली छतों पर सोलर पैनल लगाए जा सकें।

इसके अलावा, सरकारी भवनों का पूर्ण उपयोग कर, रूफटॉप सौर स्थापना करना 'पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना' (PMSG: MBY) के घटकों में से एक है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न के कार्यान्वयन मॉडल बताए गए हैं और नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों को लगाने का अनुभव रखने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि वे केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भवनों पर रूफटॉप सौर स्थापना करने में उनकी सहायता कर सकें।

तथापि, सरकारी भवनों के लिए कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध नहीं है क्योंकि सीएफए के बिना भी रूफटॉप सौर संयंत्रों की संस्थापना उनके लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात ओरेडा (OREDA) लिमिटेड, ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 38.12 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 3,163 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित की गई हैं।

इसके अलावा, बिजली की अनुबंध मांग और किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर पहले चरण में रेस्को (RESCO) मॉडल के तहत कार्यान्वयन के लिए 1,960 से अधिक सरकारी भवनों की पहचान की गई है और किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 925 भवनों को रूफटॉप सौर स्थापनाओं के लिए व्यवहार्य पाया गया है, जिसमें कुल अनुमानित सौरीकरण आवश्यकता 79.56 मेगावाट है।

*****